IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.4145 of 2019

==========

Neyaz Ahmad @ Neyaj Ahmad Son of Late Reyaz Ahmad R/o Village- Behara (Jhumka) P.O. Bahera, District-West Champaran

... ... Petitioner/s

Versus

1. The State of Bihar through Principal Secretary Human Resources Development Department, Bihar, Patna
2. The Secretary Finance Department, Bihar, Patna
3. The Special Director, Secondary Education, Bihar, Patna
4. District Education Officer, Champaran
5. The District Programme Officer, Champaran

... ... Respondent/s

==========

Appearance :
For the Petitioner/s : Mr. Raj Nandan Prasad, Advocate
For the Respondent/s : Mr. Jitendra Kumar Roy 1 (SC-13)

==========

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE BIRENDRA KUMAR
ORAL JUDGMENT
Date : 28-01-2021

The petitioner seeks for issuance of command against the respondents to pay the leave encashement, gratuity and other retiral benefit to the petitioner.

2. Indisputably the petitioner retired from the post of teacher on 31.05.2013 from recognized Madarsa Mazharul Uloom at Parsa, P.O. Marjadwa, District- West Champaran.

3. The question for consideration is whether a teacher employed in non-government aided minority school is entitled for retiral benefit.

4. Learned counsel for the petitioner has placed

WEB COPY

reliance on the resolution of the State Government bearing No.237 dated 20.02.1990, a copy at Annexure-1, as well as Memo No.2 dated 09.01.1990, a copy at Annexure-2, for his submission that petitioner is entitled for all the benefits including retiral benefits at par with the government school teachers.

5. On the other hand, learned counsel for the State-respondents contends that in the counter affidavit they have distinguished between the minority institution and the Madarsa. However, learned counsel could not explain when he was confronted with use of the word 'Madarsa' in resolution No.237 dated 20.02.1990 which reads as follows:

"बिहार सरकार, मानव संसाधन विकास, संकल्प ज्ञापांक 237 दि0 20. 2.90

विषयः– राज्य के मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अल्पसंख्यक प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों, प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों एवं प्रस्वीकृत मदरसों के शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सरकारी शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की तरह वेतन, भत्ता एवं अन्य वित्तीय सुचिधायें प्रदान करने के संबंध में।

पढ़ा गया – राजकीय संकल्प सं0 2022 दि0 18.8.79, 179 दि0 22.11.81, 522 दि0 28.2.82, 172 दि0 24.3.84, 330 दि0 16.3.84, 273 दि0 25.3.89, 300 दि0 31.3.82, 372 दि0 13.4.83, 172 दि0 24.4.83 एवं 360 दि0 31.3.84.

राज्य के प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक अल्पसंख्यक विद्यालयों, प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सरकारी

WEB COPY

शिक्षकों की भंति वेतन के अतिरिक्त अन्य सुविधयें प्रदान करने की मांग आती रही है। इन विद्यालयों एवं मदरसों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का वेतन के अतिरिक्त दी जा रही महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, आवास भत्ता, नगर क्षति पूर्ति भत्ता आदि को सुविधाओं में एकरूपता नहीं है। जहां माध्यमिक अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सरकारी शिक्षकों की भांति महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जा रहा है वही प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त केवल 13 (तेरह) किस्त एवं मदरसों को पूर्ण महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है। परन्तु आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता नहीं मिल रहा है।

2. विभिन्न अल्पसंख्यक विद्यालयों, प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों एवं प्रस्वीकृत मदरसों के शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को समान रूप में सुविधयें उपलबध कराने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन थी। सरकार द्वारा इसपर पूर्णरूपेण विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि राज्य के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राथमिक, मध्य एवं माध्यमिक विद्यालयों तथा प्रस्वीकृत गैर सरकारी संसकृत विद्यालयों एवं मदरसों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त वे सभी सुविधायें दी जाय जो सरकारी विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को उपलब्ध हैं एवं समय–समय पर जो राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाय।

3. उपरोक्त निर्णय दिनांक 1.1.90 से प्रभावी होगा।

4. इस पर होने वाले व्यय के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किया जायेगा।

5. संकल्प में वित्त विभाग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है।”

6. The aforesaid resolution makes it apparent that the State Government resolved to implement with effect from

WEB COPY

01.09.1990 different facilities including salary and retiral benefit to the recognized non-government aided minority primary/middle/secondary schools, non-government Sanskrit Schools and Madarsa of the State at par with the teachers of the government schools. Therefore, there is nothing to deny the claim of the petitioner.

7. Hence, the respondents are directed to make payment of entire retiral dues to the petitioner within a period of three months from the date of receipt/production of a copy of this order, failing which the respondent would be liable to pay interest of 8% per annum on delayed payment till its actual payment.

8. Accordingly, this application stands allowed.

(Birendra Kumar, J)

Mkr./-

AFR/NAFR	NAFR
CAV DATE	
Uploading Date	01.02.2021
Transmission Date	

WEB COPY